जबलपुर में फारेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट

†४१९. **पंडित भवानी प्रसाद तिवारी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) जबलपुर में फारेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट के खोले जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में नियुक्त तदर्थ समिति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

t [FOREST RESEARCH INSTITUTE AT JABALPUR

*419. PT. BHAWANIPRASAD TIWARY; Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleasec to state:

(a) the progress so far made with regard to the opening for a forest Research Institute at Jabalpur and the details of the *ad-hoc* committee appointed for the purpose; and

(b) by when the work is likily to be started?]

THE DEPUTY MINISTER IM THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI C. SUBRAMANIAM) : (a) An *ad hoc* Committee, consisting of officials, was set up to make recommendations to the Government on the possible site or sites for the project.

The Committee inspected, on 13th October, 1964 certain sites offeied by the Government of Madhya Pradesh for the location of the proposed Research Centre. None of the sites inspected by the Committee was found to be suitable. During discussions, the Government of Madhya Pradesh promised to suggest alternative sites. The suggestions of tne State Government are awaited.

(b) The work will be started after the site to be proposed by the Madhya Pradesh Government has been inspected anj selected and details are prepared by the Committee and approved by Government.

‡[**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण)** : (क) परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान अथवा स्थानों के सम्बन्ध में सरकार को सिफारिश करने के लिए एक तदर्थ समिति जिसमें अधिकारी शामिल हैं, बनाई गई थी । १८ अक्तूबर, १९६४ को इस समिति ने प्रस्तावित अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ स्थानों का निरीक्षण किया । समिति ने जिन स्थानों का निरीक्षण किया उनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया । विचार विमर्श के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने और वैकल्पिक स्थान सुझाने का वायदा किया । राज्य सरकार के सुझावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाए गए स्थान का समिति निरीक्षण करके उसे चुनगी और इस सम्बन्ध में वह अपना विवरण तैयार कर लेगी तो सरकार द्वारा उसका अनुमोदन होने पर काम शुरू कर दिया जाएगा ।]

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : क्या मंत्री महोदय कृपा करके यह बतलाएंगे कि किन किन स्थानों का सर्वेक्षण हुआ ?

SHRI C. SUBRAMANIAM: A few-places, near Jabalpur, were inspected but now we are awaiting suggestions from the Madhya Pradesh Government fo$_r$ alternative sites.

SHRI M. P. BHARGAVA: May I know whether this proposed, institute

tC] English translation.

tC] Hindi translation.

will be a Centrally administered institute or it will be administered by the Government of Madhya Pradesh and whether it will have anything to do with the present Forest Research Institute at Dehra Dun?

SHRI C. SUBRAMANIAM; This *a* a regional institute for fresh research. It will be run by the Central Government.

*420. *[The questioner (Shri R. K. Bhuwalka) was absent. For answer,* vide col. 2689 infra.]

विधि आयोग की सिफारिशें

*४२१. **श्री राम सहाय** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६४-६५ के वर्ष में विधि आयोग ने कितने कानूनों के सम्बन्ध में सिफारिशें की थीं ; और

(ख) विधि आयोग द्वारा पुराने कानूनों के सम्बन्ध में किया जाने वाला कितना काम अभी बाकी पड़ा है ?

†[RECOMMENDATIONS OP THE LAW COMMISSION

*421. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) what is the number of legislations about which recommendations were tendered by the Law Commission in the year 1964-65; and

(b) to what extent the work regarding the old legislations still remains to be done by the Law Commission?]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI JAGANATH RAO): (a) The number of legislations about which recommendations have been tendered by the Law Commission in the year 1964 up till now is two (the Presidency-towns Insolvency Act, 1909 and the Provincial Insolvency Act, 1920); recommendations about another voluminous law, namely, the Code of Civil Procedure, 1908, are being finalised and are expected to be tendered before the close of the year 1964.

(b) As the number of Central Acts in force is well over six hundred, it cannot be stated precisely how many of them would require revision without first examining them. Amongst the important subjects which still remain to be revised are the following:—

(i) The Indian Penal Code, 1860;
(ii) The Indian Evidence Act, 1872;
(iii) The Oaths Act, 1878;
(iv) The Transfer of Property Act, 1882;
(v) The Railways Act, 1890;
(vi) The General Clauses Act, 1897;
(vii) The Code of Criminal Procedure, 1898;
(viii) The Post Office Act, 1898;
(ix) The Indian Stamp Act, 1899;
(x) The Indian Succession Act, 1925; and
(xi) Capital Punishment.

†[**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) जिन विधियों के बारे में विधि आयोग द्वारा १९६४ के वर्ष में अब तक सिफारिशें दी गई हैं उनकी संख्या दो है [प्रेसीडेंसी नगर शोधा-क्षमता अधिनियम, १९०९ (प्रेसीडेंसी टाउन्स इनसालवेंसी ऐक्ट, १९०९) और प्रान्तीय शोधाक्षमता अधिनियम, १९२० (प्राविशियल इनसालवेंसी ऐक्ट, १९२०)]; दूसरी वृहत् विधि, अर्थात् सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८) की बाबत सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और आशा की जाती है कि वे १९६४ का वर्ष समाप्त होने के पूर्व दे दी जायेंगी ।

t [ ] English translation.

†[ ] Hindi translation.